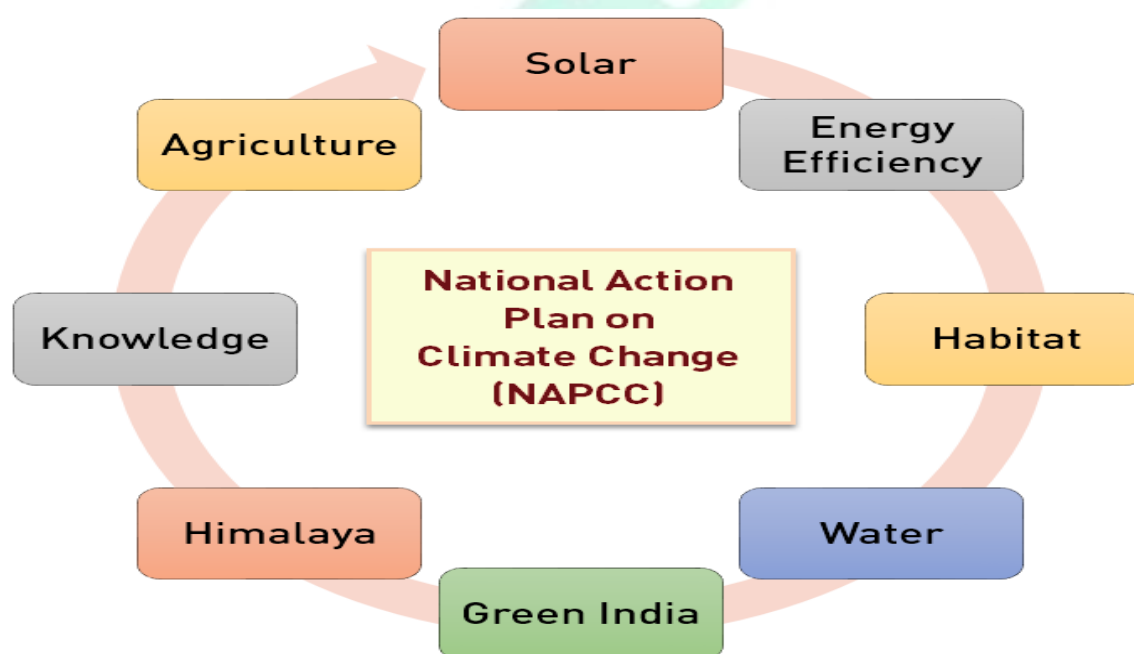


जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना

- जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) वर्ष 2008 में शुरू की गई थी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- एन.ए.पी.सी.सी. के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-आयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये आठ मिशन हैं:



- राष्ट्रीय सौर मिशन
- राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन
- राष्ट्रीय स्थायी निवास मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन हेतु राष्ट्रीय मिशन
- हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन

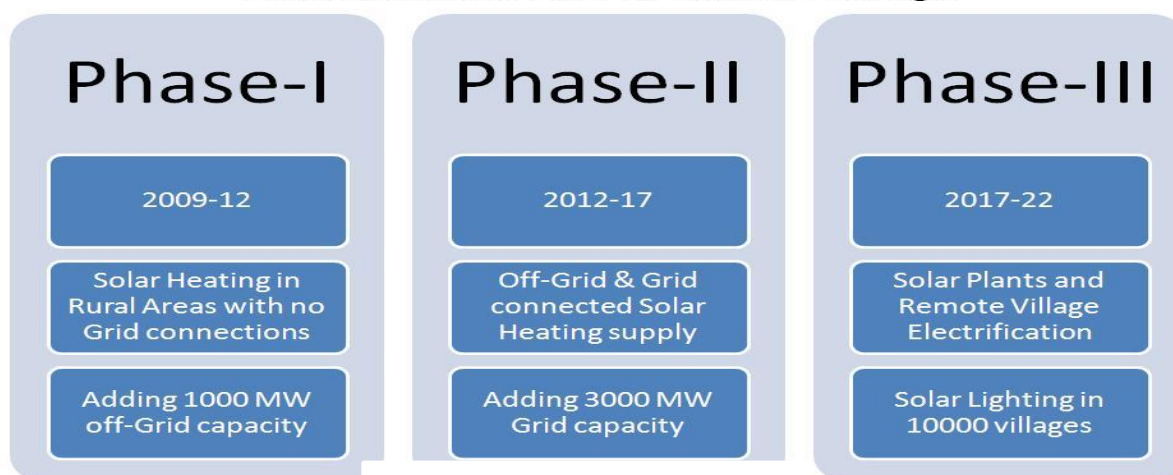
एन.ए.पी.सी.सी. निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है-

- विकास के माध्यम से समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना जो समावेशी और सतत विकास रणनीति है, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
- पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्राप्त करना।
- बड़े पैमाने पर और त्वरित गति से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करना
- सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और बाजार के नए और नवीनतम रूपों को तैयार करने के लिए विनियामक और स्वैच्छिक तंत्र।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नागरिक समाज और स्थानीय सरकारों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संबंधों का उपयोग करके योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के अंतर्गत एक वैश्विक आई.पी.आर. शासन द्वारा समर्थित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषण द्वारा सक्षम किए गए डेटा और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, साझाकरण और हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आमंत्रित करना

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

- इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
- वर्ष 2022 तक ग्रिड अनुरूपता और समानता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ और वर्ष 2030 तक कोयला आधारित थर्मल पावर को हटाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

National Action Plan on Climate Change



Jawaharlal Nehru National Solar Mission

- यह सस्ती और सुविधाजनक सौर ऊर्जा के उत्पादन द्वारा ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत वितरण को बढ़ावा देने, आर एंड डी प्रयासों को बढ़ाने के उपायों को अपनाता है।
- स्थानीय स्तर पर सौर पैनलों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ स्थानीय अनुसंधान के साथ समन्वय पर जोर देता है।
- इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की लागत को कम करना है जिससे कि यह सस्ती हो सके।

कार्य और लक्ष्य

- पहले से ही सिद्ध और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सौर ऊष्मायन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इमारतों में सौर वॉटर हीटर को अनिवार्य करना
- सुदूर गांव के विद्युतीकरण कार्यक्रम के द्वारा बिजली से वंचित गरीबों को बिजली प्रदान करने के लिए एक ऑफ-ग्रिड समाधान के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करना
- सौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए स्थितियों का निर्माण करना और पहले से ही चल रहे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करना
- इसका अंतिम उद्देश्य भारत में एक सौर उद्योग विकसित करना है, जो सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पुनः जीवाश्म ईंधन विकल्प प्रदान करने में सक्षम है।
- यह उम्मीद है कि तीसरे चरण, 2022 के अंत तक, भारत को 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सम्मेलन

- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था।
- इसे मानव पर्यावरण पर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है।
- इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया है।

ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट (हमारा सामान्य भविष्य)-1987

- सतत विकास का विचार दिया अर्थात् वह विकास, जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।

- ब्रुन्डटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने माना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गरीबी में कमी, लिंग समानता और धन पुनर्वितरण के रूप में मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण था।
- ब्रुन्डटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने माना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गरीबी में कमी, लिंग समानता और धन पुनर्वितरण के रूप में मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण था।

यू.एन.सी.ई.डी. या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के रूप में जाना जाता है
- पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पर्यावरण और विकास को एकीकृत करने की आवश्यकता के संदर्भ में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा है।
- 190 से अधिक देशों ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपना योगदान देने के आयोजन में भाग लिया है।
- अनुवर्ती के रूप में, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (रियो+10) को 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन भी रियो में आयोजित किया गया था और इसे सामान्यतः रियो+20 या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 भी कहा जाता है।

यहां जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, वे हैं:

- जहरीले घटकों के उत्पादन की जाँच करना जैसे कि गैसोलीन में लेड या रेडियोधर्मी रसायनों सहित जहरीले अपशिष्ट की जांच करना
- जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज सामने आए हैं:

1. **रियो घोषणापत्र:** भविष्य में सतत विकास में देशों का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांत
2. **एजेंडा 21:** यह सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर-बाध्यकारी कार्य योजना थी।

- i. यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर की व्यक्तिगत सरकारों के लिए एक कार्यवाई एजेंडा है, जिसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
- ii. एजेंडा 21 में "21", 21वीं सदी को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना है। एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्वयं का स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए।



3. **वन सिद्धांत:** सभी प्रकार के वनों के संरक्षण और सतत विकास पर गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ है।

रियो घोषणापत्र

1. रियो + 10 (2002)

- i. यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था।
- ii. यह एजेंडा 21 के पूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख करता है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित करता है।
- iii. यह रियो शिखर सम्मेलन का 10 वर्ष का अनुवर्तन था।

2. रियो + 20 (2012)

- i. रियो+20 ने पिछले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए पुष्टिकरण की मांग की है और एजेंडा 21 में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करके अगले 20 वर्षों के लिए वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित किया है।

ii. यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का 20 वर्ष का अनुवर्तन का था।

रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) कहा जाता है।

- जोहानेसबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 को सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है।
- रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.एस.डी.) कहा जाता है।

- शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौता था, जिसके परिणामस्वरूप **क्योटो प्रोटोकॉल** और **पेरिस समझौता** हुआ था।

दो कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते थे, जिन पर इस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

1. जैविक विविधता सम्मेलन को सी.बी.डी. कहा जाता है।
2. मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को यू.एन.सी.सी.डी. कहा जाता है।

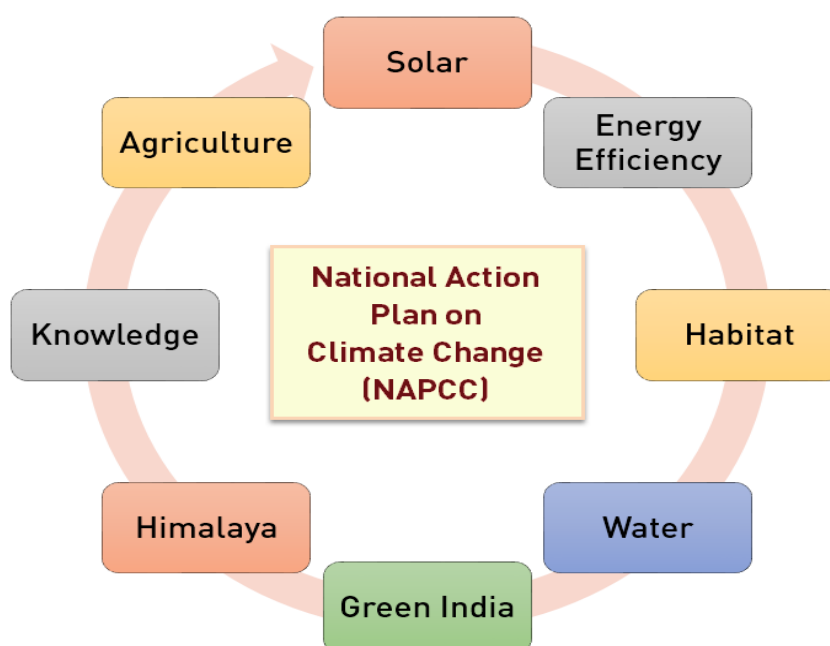
यू.एन.एफ.सी.सी.सी.: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन

- यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। इसकी वर्तमान सदस्यता 197 देशों की है।
- यह प्रोटोकॉल नामक उन महत्वपूर्ण संधियों की बातचीत के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य किसी भी देश द्वारा उत्पादित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करना है।
- यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का उद्देश्य "**मानवजनित कारकों**" के कारण जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वातावरण में **ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर** करना है।

NATIONAL ACTION PLAN ON CLIMATE CHANGE

- The National Action Plan on Climate Change (NAPCC) was launched in the year 2008 by the Prime Minister's Council on Climate Change.
- The main aim of the plan is creating awareness among the representatives of the public, different agencies of the government, scientists, industry and the communities on the threat posed by climate change and the steps to counter it.
- There are eight national missions under the NAPCC which represent multi-pronged, long term and integrated strategies for achieving key goals in climate change.

The eight missions are:



- National Solar Mission
- National Mission for Enhanced Energy Efficiency
- National Mission on Sustainable Habitat
- National Water Mission
- National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem
- National Mission for A Green India
- National Mission for Sustainable Agriculture
- National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change

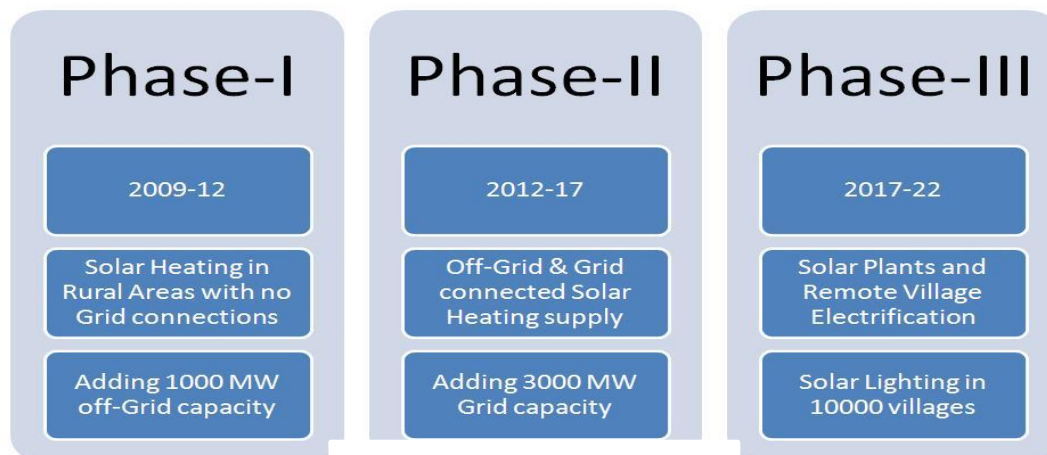
NAPCC is guided by following principles-

- Protection of poor and vulnerable sections of society through the development that is inclusive and sustainable development strategy, sensitive to climate change.
- To achieve national growth through qualitative changes enhancing ecological sustainability.
- Using o appropriate technologies for both adaptation and mitigation of GreenHouse Gases emissions extensively and at an accelerated pace.
- Regulatory and voluntary mechanisms for promotion of sustainable development and to engineer newer and innovative forms of market.
- Effective implementation of plans using linkages with various sections of society like civil society and local governments through public-private partnership.
- Inviting international cooperation for research, development, sharing and transfer of data and technologies enabled by sufficient funding and backed up by a global IPR regime under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Jawaharlal Nehru National Solar Mission

- It is launched by the Ministry of New and Renewable Energy.
- launched in the year 2010 with the primary aim of achieving grid parity and equality by 2022 and with the removal of coal-based thermal power by 2030.

National Action Plan on Climate Change



Jawaharlal Nehru National Solar Mission

- It Aims to increase the share of solar energy in the energy mix.
- It adopts the measures of increasing R&D efforts, promoting the decentralised distribution of energy by the generation of cheaper and convenient solar power.
- Emphasis on manufacturing the solar panels at the local level and synching of local research with the international efforts.
- It aims to reduce the cost of solar energy to make it affordable.

Functions and Goals

- Making solar water heaters mandatory in buildings to promote the already proven and commercially viable solar heating systems.
- By the remote village electrification programme, using solar power as an off-grid solution to provide power to the power deprived poor.
- To Create conditions for research and application in the field of solar technology and support & facilitate the already on-going R&D projects.
- The ultimate objective is to develop a solar industry in India, capable of delivering solar energy competitively against the fossil fuel options.
- It is expected that by the end of the third phase, 2022, India should have installed 20,000 MW of solar power.

United Nation conference on human development

- The United Nation Conference on human development was held in Stockholm, Sweden, in 1972
- Also known as **The Declaration on the Human Environment**.
- It set out the principles for various international environmental issues, natural resource management, pollution prevention and the relationship between the environment and development.

The Brundtland Report (Our common future) - 1987

- Gave the idea of **sustainable development**, i.e. development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

- The Brundtland Commission Report recognised that human resource development in the form of poverty reduction, gender equity, and wealth redistribution was crucial to formulating strategies for environmental conservation.
- The Brundtland Commission Report recognised that human resource development in the form of poverty reduction, gender equity, and wealth redistribution was crucial to formulating strategies for environmental conservation

UNCED or Earth Summit 1992, Rio De Janeiro Brazil

- **The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)** famously called as the **Earth Summit 1992**
- **Earth Summit 1992** succeeded in raising public awareness of the **need to integrate environment and development**.
- More than 190 countries participated in the event pledging their contribution for the sustainable development targets at the national and local level.
- As a follow-up, the **World Summit on Sustainable Development (Rio+10)** was held in **2002** in **Johannesburg, South Africa**.
- **United Nations Conference on Sustainable Development** was also held in Rio and is also commonly called **Rio+20** or **Rio Earth Summit 2012**.

The issues which were discussed here were:

- Checking production of toxic components, such as **lead in gasoline**, or poisonous waste including radioactive chemicals,
- What could be the alternate sources of energy developed to replace the fossil fuels.

The Earth Summit resulted in the following documents:

1. **Rio Declaration:** principles intended to guide countries in future sustainable development.

2. **Agenda 21:** It was a non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development.
- It is an action agenda for the UN, and other multilateral organizations, and individual governments around the world that can be executed at local, national, and global levels.
 - The "21" in Agenda 21 refers to the 21st century. Its aim is achieving global sustainable development. One major objective of the Agenda 21 initiative is that every local government should draw its own local Agenda 21.



3. **Forest Principles:** Non-legally binding document on Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests.

RIO DECLARATION

1. RIO+ 10 (2002)

- It was held in Johannesburg, South Africa
- It mentions the full implementation of the Agenda 21, overarching goal for institutions at the national, regional and international levels.

- iii. It was a 10 year follow up of RIO summit

2. RIO+20 (2012)

- i. Rio+20 sought to secure affirmations for the political commitments made at past Earth Summits and set the global environmental agenda for the next 20 years by assessing progress towards the goals set forth in Agenda 21.
- ii. It was a 20 year follow up of the Rio earth summit.

- Earth Summit 1992 held in Rio de Janeiro is called as UN Conference on Environment and Development (UNCED)
- Earth Summit 2002 held in Johannesburg) is called as the World Summit on Sustainable Development
- Earth Summit 2012 held in Rio de Janeiro) is called as the UN Conference on Sustainable Development (UNCSD)

- An important achievement of the summit was an agreement on the Climate Change Convention which in turn led to the **Kyoto Protocol** and the **Paris Agreement**.

There were two legally binding agreements which were also signed during this summit.

1. The Convention on Biological Diversity called as CBD.
2. United Nations Convention to Combat Desertification called as UNCCD.

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

- It is an international environmental treaty under the aegis of UN. It was negotiated during 1992 Earth summit. The membership now is 197 countries.

- It provides framework for negotiation of important treaties called as protocols that aim to set binding limits on the amount of greenhouse gases that can be produced by any country.
 - The objective of UNFCCC is to **Stabilize greenhouse gas concentrations** in the atmosphere to reduce the climate change due to “**anthropogenic factors**”

